ऑस्कर अवॉर्ड समारोह भारत के लिए दोहरी खुशी साबित हुआ। नाटू नाटू के अलावा शॉर्ट फिल्म ''द एलिफैंट विस्परर्स'' को बैस्ट डॉक्युमैंटरी शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया। पिच्चानवे ऑस्कर अवॉर्ड समारोह पर, सोमवार अल सुबह से ही सबकी निगाहें थीं। उस समय हर भारतीय खुशी से झूम उठा जब भारतीय फिल्म ''द एलिफैंट विस्परर्स'' के नाम की घोषणा बैस्ट डॉक्युमैंटरी शॉर्ट फिल्म के लिए हुई। इस फिल्म को कार्तिकी गोंज़ाल्विस ने डायरैक्ट किया है। ''द एलिफैंट विस्परर्स'' 8 दिसम्बर 2022 को रिलीज़ हुई थी। 39 मिनट की यह इंडियन अमेरिकन शॉर्ट डॉक्युमैंटरी एक दम्पति और हाथी के दो बच्चों की कहानी है। यह कहानी तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व की है, जहां यह दम्पति हाथी के दो अनाथ बच्चों को गोद लेता है और उनकी देखभाल करता है। फिल्म के निर्माता गुनीत मोंगा और अचिन जैन हैं।

इस साल 10 लाख भारतीयों को वीज़ा देगा अमेरिका

अमेरिकी दूतावास ने कहा कि, हम पहले ही इस साल 2 लाख भारतीयों का वीज़ा प्रोसैस कर चुके हैं

- **अमेरिकी दूतावास के अनुसार, साल 2022 में यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी दुनिया से करीब 90 लाख अप्रवासी वीजा प्रोसैस किए थे। इन वीजा में बिजनेस, ट्रैवल, स्टूडेंट और क्रू वीजा शामिल हैं।**
- **अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अमेरिकी दूतावास में स्टाफ बढ़ाया जा रहा है।**

वॉशिंगटन, 13 मार्च। अमेरिका की तरफ भारतीयों के लिए गुड न्यूज है। पिछले महीने अमेरिका ने भारतीयों के लिए वीजा स्लॉट खोले थे। अब एक और बार अमेरिका ने भारतीयों को एक और बड़ी सौगात दी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह 10 लाख भारतीय नागरिकों को इस साल वीजा जारी करेगा।

अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी मिशन ने पहले ही भारत में हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में दो लाख से अधिक आवेदनों को प्रोसेस किया गया है। हम 2023 में 10 लाख से अधिक गैर-अप्रवासी वीजा आवेदनों को प्रोसेस करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर हैं।

अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य दस लाख वीजा आवेदनों को प्रोसेस करना है, जिसमें सभी श्रेणियों के गैर-अप्रवासी वीजा शामिल हैं। अमेरिकी दूतावास के अनुसार, साल 2022 में यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी दुनिया से करीब 90 लाख अप्रवासी वीजा प्रोसेस किए थे। इन वीजा में बिजनेस, ट्रेवल, स्टूडेंट और क्रू वीजा शामिल हैं।

अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अमेरिकी दूतावास में स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रॉप-बॉक्स सुविधाओं के दायरे का विस्तार किया जा रहा है और भारतीय नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वीकएंड में इंटरव्यू स्लॉट खोलने की तैयारी भी की जा रही है। वीजा के लिए वेटिंग टाइम पहले ही काफी कमी आई है।

जनवरी में अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को इंटरव्यू स्लॉट देने की शुरुआत की थी। इसका मकसद करोना महामारी की वजह से वीजा के बैकलॉक को क्लियर करना था। एक बयान में अमरिकी मिशन ने बताया कि उसने भारत में मौजूद अपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद के ऑफिसों में स्टॉफ की संख्या बढ़ाई है।

मंत्री धारीवाल बोले, शहीद लाम्बा की पत्नी देवर के नाते गई, अब नौकरी मांग रही, तमाशा है क्या?

उन्होंने कहा, सांसद किरोड़ी लाल का कृत्य आतंकी से कम नहीं होता, सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी

- **विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री की इस दोनों टिप्पणियों पर जमकर हंगामा मचा, भाजपा विधायकों ने 70 मिनट तक वैल में आकर नारेबाजी की।**
- **उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''सदन में वीरांगना का चरित्र-हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, मंत्री में शर्म है कि नहीं? या तो वीरांगना के नाते जाने का सबूत मंत्री दें, नहीं तो इस्तीफा सौंपें।''**
- **स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी ने हंगामा बढ़ता देखकर सदन में शहीदों के मुद्दे पर हो रही चर्चा खत्म करवा दी, बाद में धारीवाल के शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटवाकर शांत कराया।**

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 13 मार्च। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहिताश लाम्बा की वीरांगना के देवर के नाते जाने का दावा किया। इतना ही नहीं राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के कृत्य को भी आतंकी जैसा बता दिया। धारीवाल की इन दोनों टिप्पणियों के चलते सदन में जमकर हंगामा मचा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ समेत तमाम भाजपा विधायकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए तकरीबन 70 मिनट तक वैल में नारेबाज़ी की। राठौड़ ने कहा, वीरांगना का चरित्र-हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, मंत्री में शर्म है कि नहीं? वीरांगना के नाते जाने का सबूत दें, नहीं तो मंत्री अपना इस्तीफा सौंपे। सांसद को आतंकी कह रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा।

सदन में हंगामा बढ़ता देखकर स्पीकर डॉ. सी.पी.जोशी ने शहीदों के मुद्दे पर हो रही चर्चा खत्म करवा दी, बाद में धारीवाल के शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटवाकर मामला शांत कराया।

दरअसल सोमवार को शून्यकाल में आधा दर्जन विधायकों ने बीते 10 दिनों से राजधानी जयपुर में धरने पर बैठी वीरांगनाओं का मुद्दा उठाया था। जिस पर स्पीकर डॉ. सी.पी.जोशी ने दोपहर 2 बजे अलग से चर्चा करवाने और सरकार की तरफ से जवाब दिलाने की व्यवस्था दी।

संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए सदन में कहा कि, ''शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी का देवर तो पहले से शादीशुदा था। उसके दो बच्चे हैं। फिर लाम्बा की पत्नी देवर के नाते चली गई। अब नाते जाकर कहती है कि मेरे देवर को नौकरी दो। भाई वाह, तमाशा है क्या? कहीं ऐसा हुआ है कि नियमों के खिलाफ किसी को नौकरी मिल गई हो। नियम के तहत जिसे नौकरी मिलनी होगी, उसे मिलेगी। जो शहीद हुए, उसके दोनों बच्चे मौजूद है। नौकरी पर हक उनका है। इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेंकने से काम नहीं चलेगा।

इसके बाद धारीवाल ने सांसद किरोड़ीलाल के कृत्य को आतंकी करार दिया। उन्होंने कहा राजनीति में रुचि लेने वाला हर व्यक्ति जानता है कि किरोड़ीलाल जिस प्रकार का कृत्य करते हैं। वह किसी आतंकी से कम नहीं होता। किरोड़ीलाल जैसा सांसद नियम जानते हुए भी नियम के खिलाफ जाकर आंदोलन करे, शांति भंग करने की कोशिश करें। कैसे बर्दाश्त करेंगे। कानून की पालना करने वाली सरकार यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।

धारीवाल के कमेंट पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि एक वीरांगना के लिए यह बात कह देना कि नाते चली गई। बहुत गलत है। आप मेरा इस्तीफा रख लीजिए। मंत्रीजी, क्या आप में थोड़ी भी शर्म नहीं है? एक वीरांगना का चरित्र हनन करेंगे। उस पर कीचड़ उछालेंगे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके पास क्या सबूत है कि नाते चली गई? हम वीरांगना का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप एक सांसद को आतंकी कह रहे हैं।

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा कि वीरांगनाओं को अस्पताल ले जाने की बात कहकर धरने से उठाया। फिर गांवों में ले गए। वीरांगना मंजू जाट से इतनी मारपीट की गई कि वह बोल नहीं पा रही थी। आप वीरांगनाओं से मारपीट करवाते हो। वादाखिलाफी करते हो। वीरांगनाओं से अत्याचार करोगे। कौन कल देश की रक्षा करने सेना में जाएगा? वीरांगनाओं से मारपीट करने वाले और वादाखिलाफी करने वाले देशद्रोही हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

भाजपा विधायक रामलाल शर्मा, कालीचरण सराफ ने कहा कि पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से सरकार के मंत्रियों ने वादे किए थे। वे वादे ही तो याद दिला रही थीं। मंत्री शहीदों के अंतिम संस्कार के वक्त परिजन नौकरी देने का वादा करके आए थे।

धारीवाल के कमेंट पर भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ समेत तमाम भाजपा विधायकों ने वैल में उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में हंगामा बढ़ता देखकर स्पीकर डॉ. सी.पी.जोशी ने मंत्री के इस जवाब के बाद जनजाति क्षेत्रीय विकास और महिला बाल विकास की अनुदान मांगों पर बहस शुरू करवा दी। भाजपा विधायकों ने वैल में आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही करीब छह विधायक अनुदान की मांगों पर बोलते रहे।

इससे पहले धारीवाल ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि वीरांगनाओं के मुद्दे पर सांसद किरोड़ीलाल पहली बार धरने पर बैठे तो उस वक्त गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से वार्ता हुई। उसमें वे मान गए और 15 दिन दे दिए। पर उस बात से पलट गए, जैसी इनकी आदत है। बाद में इन्होंने कहा कि सीएमओ के अफसर से मिलवाइए। सीएम सचिव आरती डोगरा से वार्ता करवाई गई। वे इससे संतुष्ट हो गए, धरना खत्म करने पर सहमत हो गए। लेकिन फिर पलट गए। बाद में वीरांगनाओं के साथ सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 6 मार्च को वीरांगनाएं सचिन पायलट से मिली। पायलट ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर वे उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गईं। किरोड़ी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे रहे। गत 9 मार्च को किरोड़ी ने बिना अनुमति कूच किया। प्रदर्शन किया, इस पर उनके और समर्थकों के खिलाफ सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज किया। किरोड़ीलाल के वीरांगना मंजू के गांव जाने से वहां शांति को खतरा था। उन्हें सामोद में रोका गया। वहां उनके समर्थकों ने पुलिस से बदसलूकी की। किरोड़ीलाल और समर्थकों को वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने समझाया, लेकिन उन्होंने गाली गलौच की। इस पर पुलिस ने उन्हें हटाया।

रास्ते में बीपी (ब्लड प्रेशर) की शिकायत होने पर उन्हें गोविंदगढ़ अस्पताल ले जाया गया था। सामोद थाने में मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद भाजपा के प्रदर्शन में जयपुर में पुलिस की तीन गाड़ियां तोड़ी गई, इस पर अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया है।

वन रैंक वन पैंशन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने उस संदेश को तुरन्त वापस ले, जिसमें कहा गया था कि ओ.आर.ओ.पी. एरियर्स चार किश्तों में दिया जायेगा।

अटॉर्नी जनरल और वेंकटरामानी ने कहा कि केन्द्र पूर्व सैनिकों को ओ.आर.ओ.पी. की पहली किस्त का भुगतान कर चुका है लेकिन आगे और भुगतान करने के लिये उसे कुछ और समय चाहिये।

बैंच ने वैंकटरामानी से कहा, ''पहले ओ.आर.ओ.पी. के भुगतान से संबंधित (अपनी) 20 जनवरी की अधिसूचना को वापस लीजिये, उसके बाद ही, हम समय संबंधी आपकी अर्जी पर विचार करेंगे।''

बैंच ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की 20 जनवरी की अधिसूचना उसके (अदालत) के निर्णय के पूरी तरह विपरीत थी।

बैंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे एक नोट तैयार करें, जिसमें किये जाने वाले भुगतान की मात्रा, भुगतान के लिये अपनाये जाने वाले तरीको का विस्तृत विवरण दिया जाये तथा यह भी बताया जाये कि एरियर्स के भुगतान के समय एवं राशि की प्राथमिकताएं क्या होंगी।

शीर्ष अदालत एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमैंट (आई.ई.एस.एम. द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई कर रही है। याचिका में आई.ई.एस.एम. ने माँग की है कि रक्षा मंत्रालय की 20 जनवरी की अधिसूचना रद्द कर दी जाये। 27 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने सशस्त्र सेनाओं के पात्र पेंशनरों को ओ.आर.ओ.पी. एरियर्स के भुगतान में विलम्ब को लेकर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की थी तथा संबंधित सचिव से ऐसी अधिसूचना जारी करने का स्पष्टीकरण माँगा था, जिस अधिसूचना में अदालत द्वारा तय की गई भुगतान की टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया था। 9 जनवरी को शीर्ष अदालत ने ओ.आर.ओ.पी. के कुल एरियर्स के भुगतान के लिये केन्द्र को 19 मार्च तक का समय दिया था।

लेकिन 20 जनवरी को रक्षा मंत्रालय ने ऐसी अधिसूचना जारी कर दी थी कि एरियर्स चार वार्षिक किश्तों में दिये जायेंगे।

बी.बी.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा कि ''बी.बी.सी. के लिए निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। जब लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एवं ऑडिएन्सेस के साथ विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट्स व ऑन एयर पोज़ीशन्स दी जाती हैं तब बिगड़ी स्थिति को पटरी पर लाने के लिए संतुलन स्थापित करना कठिन होता है।''

उन्होंने आगे कहा कि लिनेकर जैसे फ्रीलांसर्स सहित सोशल मीडिया गायडैन्स को कैसे संचालित किया जा सकता है, उस पर एक स्वतंत्र रिव्यू किया जाएगा।

अलवर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रोजैक्ट की फंडिंग भी शामिल है, संबंधित एयरपोर्ट डैवलपर और संबंधित राज्य सरकारों की होगी बशर्ते एक राज्य सरकार ने प्रोजैक्ट प्रस्तावित किया हो। जनरल सिंह ने कहा कि देश भर में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने हैं। इनमें से 11 पहले से काम कर रहे हैं। ये है- शिर्डी, कन्नूर, पकयोंग, कलबुर्गी, ओरवकाल (कुर्नूल) सिंहदुर्ग, कुशीनगर, इटा नगर, मोपा, शिवा मोगा।

सिलिकॉन वैली बैंक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विफल होने से एक विषम चक्र चलने की आशंकाएं पैदा कर दी हैं। तथापि यह विफल बैंकों के एक गंभीर पतन के बजाए वर्ष 2008 के ग्लोबल फायनैंशियल संकट की याद अधिक ताजा करता है। वर्तमान के बैंक वर्ष 2008 के बैंकों की तुलना में कहीं अधिक कैपिटलाइज्ड और मैनेज्ड हैं तथा रैग्यूलेटर्स ने आश्वस्त किया कि किसी प्रकार के चेन रिएक्शन की आशंका नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी बैंकों की विफलता के प्रति निराशाजन प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।

यद्यपि सभी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि एस.वी.बी. की विफलता का भारतीय बैंकिंग सैक्टर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी इनकी खबर ने निवेशकों के मनोभावों पर एक मनोवैज्ञानिक असर डाला। प्राइवेट सैक्टर के कुछ बैंकों सहित बैंकों के शेयर भावों में भारी गिरावट आई।

फिर भी, भारत का बैंकिंग सैक्टर किसी बुरी स्थिति से फिलहाल थोड़ा सुरक्षित महसूत कर रहा है।

महंगाई की वर्तमान दर ट्रैंड में मामूली सुधार दर्शा रही है। यह दर 6.5 प्रतिशत से गिरकर 6.44 प्रतिशत पर आ गई है। तथापित महंगाई का वर्तमान स्तर रिज़र्व बैंक द्वारा तय सहनशक्ति के स्तर से ऊपर चल रहा है।

आर.बी.आई. ने महंगाई का लक्ष्य 4 प्रतिशत, यानि कि 2 प्रतिशत प्लस या माइनस तय किया था। उसके हिसाब से वर्तमान महंगाई दर आर.बी.आई. के टॉलरैन्स बैण्ड से अधिक है।

यद्यपि, अमेरिकी बैंकों की विफलता और आम निराशा से निर्मित संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उम्मीद है कि आर.बी.आई. महंगाई का मुकाबला करने के लिए ब्याज दर में फिलहाल और कोई वृद्धि नहीं करेगा।

ब्याज दर में की जाने वाली कोई भी वृद्धि प्राय: बैंकों के असैट पोर्टफोलियो पर विपरीत असर डालती है क्योंकि बैंकों के पास आमतौर पर बॉण्ड्स के फार्ज बैग होते हैं और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तब बॉण्ड्स का मूल्य प्रभावित होता है।

बैंकों की विफलता की खबरों के बाद सरकार भी सक्रिय हो रही है। एस.वी.बी. के ध्वस्त होने के बाद किसी संभावित कठिनाई को कम करने को लेकर सरकार भारतीय स्टार्ट अप्स के बारे में सोच रही है, क्योंकि बताया जाता है कि अधिकांश स्टार्ट अप्स ने अपने फण्ड्स एस.वी.बी. में रखे हुए थे।

'पहली बार देखा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा- दोनों ही सदनों में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इंगलैंड में लोकतंत्र को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे।

लोकसभा में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गत सप्ताह राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र पर की गई टिप्पणियों को लेकर उनकी आलोचना की तथा भाजपा सदस्यों द्वारा किये जा रहे राहुल-विरोध को नेतृत्व प्रदान किया। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने राजनाथ सिंह का समर्थन करते हुये, माँग की कि राहुल गांधी अपनी टिप्पणियों के लिये माफी माँगें। दोनों सदन सुबह ही अपरान्ह 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दिये गये, किन्तु उसके बाद, जब दोनों ही तरफ से हंगामा और शोर-शराबा जारी रहा, तो सदन पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिये गये। पहले स्थगन से पूर्व, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों में सत्ता पक्ष की नारेबाजी के जवाब में, अपनी पुरानी माँग दोहराई कि प्रधानमंत्री मोदी की सहायता से गौतम अडानी के उत्थान की जाँच जॉइन्ट पार्लियामैन्ट्री कमेटी (जे.पी.सी.) से कराई जाये। राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे लम्बे समय से संसद में हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि सत्तारूढ़ पार्टी सदन को काम न करने दे, जैसा कि राहुल की क्षमा-याचना के लिए भाजपा सदस्यों की नारेबाजी में दिखाई दे रहा था।

समलैंगिक विवाह के मुकदमे की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा

अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वृहद बैंच करेगी

- **मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की बैंच ने सोमवार को मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को संविधान बैंच के समक्ष विचार के लिए भेजने का फैसला सुनाया।**

नई दिल्ली, 13 फरवरी (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगी और इस अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजने का फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संविधान पीठ 18 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 145 (3) का इस्तेमाल करेंगे और पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा इस मामले का फैसला किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के समक्ष मामले को अंतिम सुनवाई के लिए भेजते हुए कहा कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के परस्पर प्रभाव के मद्देनजर यह मुद्दा मौलिक महत्व का है।

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष तर्क देते हुए कहा कि प्रेम, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार को पहले ही उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। कोई भी उन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन जहां तक विवाह का अधिकार प्रदान करने का सवाल है यह तो विधायिका के विशेष क्षेत्र में आता है।

मेहता ने हालांकि कहा कि यदि एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में विवाह समान लिंग के बीच आता है तो गोद लेने पर सवाल आएगा और इसलिए संसद को बच्चे के मनोविज्ञान के मुद्दे को देखना होगा।

भारत को एक साथ मिली दो ऑस्कर पुरस्कार जीतने की खुशी

''आर.आर.आर.'' फिल्म के गाने नाटू-नाटू को बैस्ट ओरिजनल सॉन्ग कैटगिरी में तथा ''द एलिफैंट विस्परर्स'' फिल्म को बैस्ट डॉक्यूमैंटरी शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड प्राप्त हुआ है

- **ऑस्कर अवॉर्ड्स में जीत का परचम लहराने वाली डॉक्यूमैंटरी फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स की हर ओर तारीफ हो रही है। ऑस्कर अवॉर्ड जीतने के बाद फिल्म सोशल मीडिया पर छाई हुई है। 39 मिनट की इस फिल्म में इंसान और जानवर के बीच के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया है।**
- **''द एलिफैंट विस्परर्स'' फिल्म मात्र 39 मिनट की है लेकिन इसे बनाने में फिल्म की टीम को 5 साल मेहनत करनी पड़ी है।**

नई दिल्ली, 13 मार्च (वार्ता)। भारत की झोली इस बार ऑस्कर पुरस्कारों से भर गई है, एक साथ भारत को दो ऑस्कर अवॉर्ड प्राप्त हुये हैं। फिल्म ''आर.आर.आर.'' के नाटू-नाटू सॉन्ग को बैस्ट ओरिजनल सॉन्ग का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। इसके अलावा द एलिफेंट व्हिस्परर्स ने सोमवार को 95वें अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। द एलिफेंट व्हिस्परर्स फिल्म का निर्माण गुनीत मोंगा ने और निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है।

इस लघु फिल्म की प्रतिस्पर्धा हॉलआउट, द मार्था मिशेल इफेक्ट, स्ट्रेंजर एट द गेट, और हाउ डू यू मेज़र ए ईयर से थी।

ऑस्कर अवॉर्ड्स में जीत का परचम लहराने वाली डॉक्युमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर्स की हर ओर तारीफ हो रही है। ऑस्कर अवॉर्ड जीतने के बाद फिल्म सोशल मीडिया पर छाई हुई है। 39 मिनट की इस फिल्म में इंसान और जानवर के बीच के खूबसूरत रिश्ते को दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी को बनाने का सफर काफी दिलचस्प रहा है।

द एलिफेंट व्हिस्पर्स को कार्तिकी गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा हैं। कुछ मिनटों की इस फिल्म की कहानी दक्षिण भारतीय कपल बोमन और बेली की है, जो रघु नाम के छोटे अनाथ हाथी की देखभाल करते हैं। इस डॉक्युमेंट्री फिल्म को तमिल भाषा में बनाया गया है, जिसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।

कहने को तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स 39 मिनट की पिक्चर है। लेकिन इसे बनाने में कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा ने पूरे पांच साल तक मेहनत की है। फिल्म की डायरेक्टर ने पांच साल तक बोमन और बेली की जिंदगी को करीब से देखा। छोटी से छोटी किसी भी जानकारी को बारीकी से गौर किया, जिसका परिणाम यह मिला कि उसे बड़ी ही खूबसूरती से फिल्म में दिखाया गया।

द एलिफेंट व्हिस्पर्स 8 दिसंबर, 2022 को रिलीज हुई थी। इस मूवी में इंसान और बेबी एलिफेंट के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। कैसे एक कपल हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उसकी देखभाल करता है।

'इलाहाबाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मस्जिद हाई कोर्ट और यू.पी. सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नवम्बर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार की बैंच ने याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी कि मस्जिद के लिए आसपास अन्य जमीन मांगने के लिए आवेदन कर सकते है। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन लीज़ पर या और लीज़ खत्म हो चुकी है इसलिए याचिकाकर्ता इस पर दावा नहीं कर सकते है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो मस्जिद प्रबंध समिति के वकील हैं, ने कहा कि यहां पर 1950 के दशक से ही मस्जिद है और इसे हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। बैंच ने कहा कि लीज़ खत्म होने के बाद मस्जिद को हटाने के लिए कहा गया है।

तेलंगाना में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का सामना पार्टी के बहुत सारे पुरुष और महिलाएं कर रहे हैं।

जिस दिन केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद आये तथा उन्होंने सभी नेताओं को मिलकर पार्टी के लिये काम करने के निर्देश दिये थे, उसके एक दिन बाद ही भाजपा के एक अन्य नेता ने सवाल खड़ा किया था कि ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिये हम कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो फिर हम वैसा ही काम कैसे कर सकते हैं।

एक राजनैतिक विश्लेषक का कहना है कि राज्य में विभिन्न पार्टियों के लोगों का भाजपा में शामिल होना यह तो दर्शाता है कि भाजपा की अंदरूनी बनावट और बुनावट में कुछ फर्क तो है। लेकिन अब भाजपा के अंदरूनी मतभेद भी सामने आ रहे हैं। राजनैतिक विश्लेषक ने कहा कि अगर भाजपा सावधान न रही तो वह अपनी वो संभावनाएं गँवा बैठेगी, जो तेलंगाना में शानदार से भी बेहतर नज़र आ रही हैं। इस बीच, शेखर राव और अरविन्द ने बान्डी संजय की उन अशोभनीय टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है जो उन्होंने के.सी.आर. की पुत्री के. कविता के खिलाफ की थीं। बान्डी संजय ने तेलुगू में कहा था, ''ई.डी. उन्हें गिरफ्तार ही करेगा और क्या, उन्हें चूमेगा?'' संजय की यही वो टिप्पणी है जो भाजपा नेताओं को भी नागवार गुजरी है। इसी सिलसिले में, राज्य महिला आयोग ने बान्डी संजय को एक नोटिस जारी कर दिया है तथा उन्हें 15 मार्च को आयोग में तलब किया है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908